



## छत्तीसगढ़ सरकार 36 घंटे भी नहीं दिए

### और उजाड़ दिया आशियाना

अब तो बताइए मुख्यमंत्री जी...क्या छापे ?

पर इंकलाब होता रहेगा इंसफ तक... 55 वां दिन

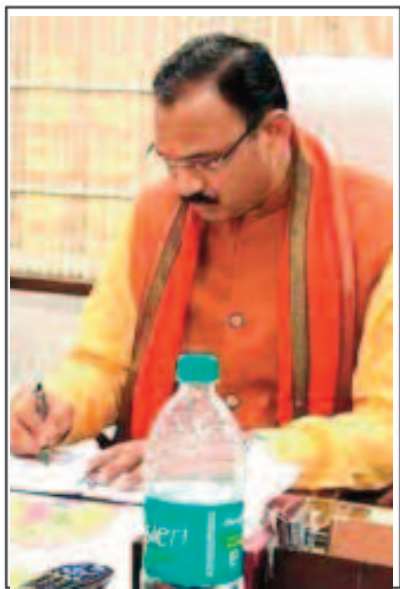


## क्या प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के लिए पूरे प्रदेश के लोगों से ऊपर उनके भतीजे हैं ?

- » छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार क्या गैर संवेदनशील सरकार है...?
- » सरकार को कमियां ना दिखाएं तो क्या दिखाएं...?
- » क्या विष्णुदेव साय सरकार बेहतर चल रही है...सिर्फ यह बात आईएस लॉबी को पता है...आम जनता को नहीं है जानकारी...?
- » किसी का दिव्यांग प्रमाण-पत्र फर्जी वह करता है मंत्री के घर मनमर्जी, दिव्यांग मांग रहे अधिकार क्या उन्हें दोगे न्याय प्रदेश के कर्णधार?
- » क्या फर्जी दिव्यांग और फर्जी डिग्री के आधार पर जो कर रहे नौकरी उन्हें होगी जेल...उन्हें मिल सकेगा संकल्प पत्र अनुसार दण्ड...?

स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों को संरक्षण देने की बात कही...वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर जनसंपर्क अधिकारी को आगे कर समाचार-पत्र पर दबाव बनाने का कर रहे वह काम...ये कैसा संरक्षण? कैसे पत्रकारों को मिलेगी सुरक्षा...कैसे समाचार-पत्र रह सकेंगे निष्पक्ष... जब उन्हें सच लिखने पर मिलेगी सजा?

## तुगलकी फरमान के विरुद्ध कलमबंद अभियान...



छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विभाग जनसंपर्क के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल के विभाग से संबंधित समाचारों के प्रकाशन पर जनसंपर्क संचालक के आयुक्त सह संचालक आईपीएस श्री मयंक श्रीवास्तव



के मौखिक आदेश पर घटती-घटना के शासकीय विज्ञापन पर रोक लगाकर दबाव बनाने से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मूलभूत हक पर कुठाराघात के विरुद्ध कलमबंद अभियान...प्रशासनिक अत्याचार झेलने के बावजूद है जारी ...

घटती-घटना के सैदी पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

# दिव्यांग संघ ने वित्तमंत्री ओपी चौधरी को भी दिया ज्ञापन

- » फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे अधिकारियों के प्रमाण-पत्र की जांच कराने की गई मांग...
- » स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी का नाम भी है शामिल फर्जी दिव्यांग बनकर नौकरी करने वालों की सूची में...
- » छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ वास्तविक दिव्यांगों को मिलने वाले लाभ के लिए लड़ रहा है लड़ाई...
- » फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले वास्तविक दिव्यांगों के अधिकारों का कर रहे हमन... इतने बड़े मामले में सरकार क्यों चुप बैठी है?



फाईल फोटो-

पर कार्यवाही करने से बच रही है... क्योंकि फर्जी दिव्यांग सरकार को अपनी मर्जी से चला रहे हैं... इतनी ऊंची पहुंच व पकड़ है कि... शिकायत कोई भी कर ले... ना जांच होगी ना कार्यवाही होगी... और सही दिव्यांग अपने हक खोते जा रहे हैं। इस समय छत्तीसगढ़ में दिव्यांग संघ फर्जी तरीके से फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे लोगों को लेकर लगातार शिकायत कर रहा है और जांच कार्यवाही की मांग कर रहे हैं ताकि सही दिव्यांगों को उनका हक मिल सके। एक बार फिर दिव्यांग संघ वित्त मंत्री ओपी चौधरी को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है और सही दिव्यांगों को उनका हक मिल सके इसकी वह लड़ाई लड़ रहे हैं बड़ा आंदोलन भी उनके तरफ से होने जा रहा है ऐसे में ही सवाल यह उठता है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी जो राज्य सेवा आयोग के अधिकारी हैं

उनकी भी नौकरी फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर लगी हुई है जिसका नाम भी दिव्यांग संघ के सूची में मौजूद है जो फर्जी अधिकारी कर्मचारी वाली ही सूची में शामिल है जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं।  
**फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र में सुविधियों में है स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी**  
स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर ही चुने गए हैं और इसके लिए उन्होंने श्रवण बाधित बनकर उसका फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनवाकर यह नौकरी हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी का दिव्यांग प्रमाण-पत्र फर्जी है यह हम नहीं कह रहे हैं यह प्रदेश का दिव्यांग संघ कह रहा है और उसका कहना है की सभी को सरकार निकालने की नौकरी से

कार्यवाही करे वरना वह बड़ा आंदोलन करेंगे क्योंकि फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनवाकर ऐसे लोग दिव्यांग लोगों का हक मार रहे हैं और वह ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर तक है। स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी की कुर्सी हथियाने वाले अधिकारी की पहुंच भी ऊंची है उनके एक भाई राज्य प्रशासनिक सेवा के ही अधिकारी हैं और वह पूर्व में मुख्यमंत्री के ओएसडी रह चुके हैं और उस समय माना जा रहा है अपने भाई को वह बचाने का काम करते थे वहीं अब खुद उनका भाई स्वास्थ्य मंत्री से जाकर इसलिए चिपक गया है उनका ओएसडी बन गया है क्योंकि उसे भी मालूम है वर्तमान सरकार में उसका बचाव एक ही व्यक्ति गलत होने के बावजूद भी कर सकता है वह खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं जो अपने

**पंजीयन क्र. 2249891 छत्तीसगढ़ शासन**  
**छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ**  
पता :- ग्राम रामगढ़, वि.खं.य जिला-भुवनेश्वरी (छ.ग.) पिन-495334  
Email : cgdivyansangh2@gmail.com

प्रदेश अध्यक्ष - शक्तिशक्ति साहू मो.8817889231 प्रदेश संचालक - लक्ष्मीकान्त यादव मो.8357835877

प्र.पत्र/ 100 दिनांक- 26.8.2024

प्रति,  
माननीय श्री ओ.पी. चौधरी जी  
मंत्री वित्त विभाग  
छ.ग. शासन

विषय- फर्जी/गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय नौकरी में लगे अभ्यर्थियों के दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण राज्य मेडिकल बोर्ड रायपुर से कराने के संबंध में।  
संदर्भ- हमारे संघ के पूर्व समस्त आवेदन/शिकायत पत्र

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि छ.ग. शासन ने वर्तमान में लगभग 50 प्रतिशत पदों पर फर्जी दिव्यांग लोग कार्यरत हैं छ.ग. में कई गैर सक्षम हे व 50 हजार से 1 लाख रुपये में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया देते हैं। कुछ केस डॉक्टरों या स्टॉफ की जानकारी में होती है लेकिन अधिकतर केस में प्रमाण पत्र बनवाते समय अन्य वास्तविक दिव्यांग को पैसा देकर पेश करते हैं जिससे डॉक्टरों के द्वारा आसानी से प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इस प्रकार से फर्जी व्यक्ति नौकरी में लग जाता है और वास्तविक दिव्यांगजन इससे वंचित रह जाता है। दिव्यांग व्यक्ति का जीवन संघर्ष से नरा होता है। वे लोग हमारे अधिकार पर लगे जाकर उनके जीवन संघर्षों से नरा होता है। वे लोग हमारे अधिकार पर लगे जाकर उनके जीवन संघर्षों से नरा होता है। वे लोग हमारे अधिकार पर लगे जाकर उनके जीवन संघर्षों से नरा होता है। वे लोग हमारे अधिकार पर लगे जाकर उनके जीवन संघर्षों से नरा होता है।

क्र	अर्थियों का नाम	जन्मतिथि	धर्म	रोज मंवर	पद का नाम	विभाग का नाम	निम्नलिखित वर्षों में भी राज्य सेवा पर कार्य किया था
							परीक्षा दिया था पर फर्जी से काम नहीं हो के कदम फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पा यहाँ वर्ष एवं रोज मंवर संवर्धन में संलग्न

कार्यकारी सदस्य  
केवल साहू  
भरत वर्मन  
नगेन्द्र वर्मा  
संद्रोहर चन्द्रा  
अर्जुन साहू  
विद्याभूषण साहू

वह फर्जी डिग्री और फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी करने वालों को नौकरी से बाहर निकालकर जेल के सलाखों के पीछे भेज पाएंगे?

**मोदी की गारंटी के नाम से आई छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार में ही डूबती जा रही है?**  
वैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की इस बार की सरकार कई बड़े वादों के साथ वापसी कर सकी है जिसमें भ्रष्टाचार को भी मिटाना उसका वादा है या जिससे उन्होंने मोदी की गारंटी का नाम दिया है लेकिन जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ रहा है यह देखने को मिल रहा है की सरकार भ्रष्टाचार में ही डूबती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में तो केवल भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है वह स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे का मामला हो या उनके ओएसडी का मामला हो जिसमें एक फर्जी डिग्री वाला सचिव अधिकारी है और भ्रष्टाचार मंचता फिर रहा है वहीं एक फर्जी दिव्यांग बनकर बड़ा अधिकारी है और स्वास्थ्य मंत्री का खास है। यदि देखा जाए तो प्रदेश में भाजपा की नई सरकार की किरकिरी केवल स्वास्थ्य मंत्री के कारण ही हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री की मनमानी और उनकी स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति जो महत्वपूर्ण पदों पर व्यवस्था के तहत की गई है वह यह साबित करता है की किस तरह चुन चुन कर भ्रष्टाचारियों को पद दिया गया जो मरीजों के हक का जितना लूट सके वह उतने ही बड़े पद पर स्वास्थ्य मंत्री की कृपा से बैठा है। उनका खुद का भतीजा तो बिचौलिया भी बन चुका है अब वह किस किस पद रखना है क्या लेना देना है वह खुद तय करने लगा है।

भतीजे की भी फर्जी डिग्री मामले में उसके भ्रष्टाचार मामले में उसके साथ खड़े हैं उसे कोरिया से भी बड़ा जिला देकर उसका मनोबल भ्रष्टाचार के लिए बढ़ा चुके हैं। अन्य कोई और उसकी मदद नहीं करेगा यह वह जानकर ही स्वास्थ्य मंत्री से जा चिपका है।

**तथा वित्तमंत्री अपनी छवि साफ सुथरी वाली इस मामले में भी बरकरार रख पाएंगे?**  
वैसे अब प्रदेश के सबसे साफ सुथरे छवि के मंत्री के रूप में अपनी

छवि जनता के बीच ले जाने वाले वित्तमंत्री के पास दिव्यांग संघ आवेदन प्रस्तुत किया है और फर्जी दिव्यांग अधिकारी कर्मचारियों पर वह कार्यवाही की मांग कर रहा है अब ऐसे में देखना है की क्या वित्तमंत्री अपनी छवि साफ सुथरी वाली इस मामले में भी बरकरार रख पाएंगे क्या

## तुगलकी फरमान के विरुद्ध कलमबंद अभियान...

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विभाग जनसंपर्क के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल के विभाग से संबंधित समाचारों के प्रकाशन पर जनसंपर्क संचनालय के आयुक्त सह संचालक आईपीएस श्री मयंक श्रीवास्तव के मौखिक आदेश पर घटती-घटना के शासकीय विज्ञापन पर रोक लगाकर दबाव बनाने से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मूलभूत हक पर कुठाराघात के विरुद्ध कलमबंद अभियान... ?

### आवाम की आवाज... घटती घटना



केशी गुमा द्वारका नई दिल्ली  
मत दबाओ आवाज़ हमारी मैं आवाज़ हूँ आवाम की सूत्र हूँ शासक जनता के बीच बातचीत का जरिया हूँ मैं हूँ आवाज़ अन्याय के खिलाफ मैं ही न्याय दिलवाती हूँ खबर बन अखबार की जनता को जगाती हूँ मेरा कर्तव्य है सच पर चलना सच से परिचय कराती हूँ घटित हुई हर घटना का सही चित्रण बतलाती हूँ मत खेलों अस्तित्व से मेरे कलमबद्ध हो यह कहती हूँ सफर पुराना है ये मेरा दूर दूर तक जाती हूँ आवाज़ बुलंद है अपनी कलम हथियार है अपना हिम्मत होसले से अपने हर सफर तय कर जाती हूँ मत दबाओ आवाज़ हमारी मैं आवाज़ हूँ आवाम की



**कलम बंद...का 55 वां दिन**

**कलम बंद...का 55 वां दिन**

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

घटती-घटना के सहेही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

## यह कैसी सरकार आ गई...शुरुआती दौर पत्रकारों के लिए बनी मुसीबत ?

- » क्या पत्रकारों से कमियां दिखाने का अधिकार मौजूदा सरकार छीन रही...
- » संविधान में मूल अधिकार का भी पत्रकार नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल ?
- » क्या संविधान से चलना भी अब इस सरकार में दूसर हो जाएगा ?

### 9 महीने वाली सरकार के कार्यकाल में पत्रकारों से जुड़े कई मामले आ गये सामने

-रवि सिंह-  
अम्बिकापुर, 25 अगस्त 2024  
(घटती-घटना)।

देश का भविष्य लोकतंत्र के चार स्तंभों पर टिका है पर क्या चार स्तंभ मजबूती से खड़े हैं या फिर एक स्तंभ के लिए दो स्तंभ मुसीबत बन खड़े हैं, चौथे स्तंभ की सुरक्षा इस समय मुख्य मुद्दा बन चुकी है संविधान का रीड की हड्डी कहे जाने वाला अनुच्छेद 19 इस समय कमजोर होता दिख रहा है, इसी पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। संविधान में अधिकार तो पर अधिकार है, संविधान पर ही खतरा मंडरा रहा है क्योंकि अनुच्छेद 19 के तहत काम करने वाले पत्रकार अधिकारों का उपयोग करके अपराधी बनते जा रहे हैं। सरकार की कमियों को इस अधिकार के तहत दिखाना उनके लिए अपराध की श्रेणी में आना हो गया? छत्तीसगढ़ के 9 महीने वाली सरकार पत्रकारों पर ही कहर बरपा रही है। वर्तमान सरकार के 9 महीने के कार्यकाल में कई पत्रकारों पर अलग-अलग तरीके से हमले हो रहे हैं। सारे हमले राजनीतिक व प्रशासनिक कहे जा रहे हैं। किस तरीके से षडयंत्र राजनीतिक प्रशासनिक हो रहे हैं कि पत्रकारों के लिए जीना मुहल हो रहा है। या तो बिकने के पत्रकारिता करने की आदत डाली जा रही है और ईमानदारी से पत्रकारिता करने वालों को अपराधी बनाया जा रहा है... जो स्वाभिमान नहीं बेच रहा वह अपराधी बन रहा... और जो स्वाभिमान बेच रहा वह सरकार के साथ चल रहा...जैसी स्थिति इस समय निर्मित है। उससे तो यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या हो रही है... और हत्या करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है संविधान की बात कहने वाले ही लोग हैं। अब इस समय पत्रकारों का ही आंदोलन शुरू हो चुका है और सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है कहीं फर्जी एफआईआर दर्ज हो रहे हैं...तो कहीं कोई विधायक खुलेआम धमकी दे रहा है...। स्थिति तो यह है कि मंत्री विधायक की कहां तक विकास करने का मार्गदर्शन दे रहा है? अब यह तोड़फोड़, अपराधी बना का चालान न जाने इस सरकार को कहां तक विकास करने का मार्गदर्शन दे रहा है? और कहां तक इस सरकार से लोगों का भरोसे की उम्मीद थमी रहेगी? यह भी सोचनीय विषय बना हुआ है। देश की दो स्तंभ तो अपने आप को इतना मजबूत समझ रहे हैं कि चौथे स्तंभ को गिराकर भी देश की जिम्मेदारी उठा लेंगे ऐसा उनका मनोबल है। क्या यही वजह है कि एक स्तंभ को नेस्तनाबूत करने के लिए दो स्तंभ काम कर रहे हैं...क्या चौथे स्तंभ की जरूरत अब देश को नहीं है... या फिर चौथे स्तंभ तीनों स्तंभों का स्वर्ण सिद्धि में बाधा बन रहा है... जिस वजह से उसे हटाना ही ज्यादा उचित है। पढ़ना आपको संविधान है पर चलना आपके लिए संविधान के तहत



काफ़ी कठिन है बात तो संविधान की होती है पर संविधान के साथ चलने में कई रोड़े आते हैं। कुछ ऐसा ही नजर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। साक्षात के उदाहरण इस समय खड़े हो चुके हैं मुह बंद करने व कलम बंद करने की तैयारी है। गांधी के देश में बुलडोजर व फर्जी प्रकरण कोई कार्यवाही माना जा रहा है। चौथा स्तंभ को अब सिर्फ उम्मीद है भी तो देश के पहले स्तंभ से यानी कि न्यायपालिका से न्यायपालिका की अब चौथे स्थान के लिए सहारा बन सकती है और चौथा स्तंभ को भी अभिनयपालिका से ही उम्मीद है।

**बदले की भावना से घटती-घटना समाचार-पत्र कार्यालय पर चला बुलडोजर**

खबरों के प्रतिशोध में जहां मौजूदा सरकार ने नियम को ही निरस्त कर दिया और शासन प्रशासन को खुली छूट दे दी एक अखबार के प्रतिशोध को नेस्तनाबूत करने की और ऐसा लगा कि उन्होंने कोई जंग जीत ली हो, लेकिन अखबार के प्रतिशोध टूटने से सरकार की छवि कितनी धूमिल होगी

**अम्बिकापुर**  
**सरकार के खिलाफ लिखना पड़ा भारी।**  
सरगुजा के स्थानीय अखबार "घटती-घटना" के कार्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। लोगों के जागने से पहले ही विलडिंग जमीदोज।



का वार्डर है। कौटा, चित्तूर के बीच अवैध उत्खनन व परिवहन का काम धड़ले से चल रहा है। अवैध उत्खनन पर समाचार कवरेज करने गये चार पत्रकार साथी बप्पी राय, धर्मेश सिंह, मनीष सिंह, निशु त्रिवेदी के वाहन पर गांजा रखकर फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज कराने में अवैध खनन माफिया और कौटा थाना प्रभारी की मुख्य भूमिका रही है। बहरहाल कौटा थाना प्रभारी को निलंबित कर जेल भेज दिया गया है। गांजा तस्करी के मामले में साजिश के तहत फर्जी तरीके से फंसाये का यह पहला मामला है। अवैध उत्खनन पर खबर बनाने गये पत्रकारों के वार्डर वाले थाने के देखरेख में अवैध उत्खनन का आरोबर फल-फूल रहा है। इसे रोका जाना आवश्यक है। संविधान में लोकतंत्र का चौथे स्तंभ के द्वारा अवैध काले कारनामों को उजागर करने एवं आम जनता, समाज के सामने सच्चाई का आईना दिखाने का कार्य

निष्पक्ष जांच और उचित कार्यवाही भी होनी चाहिए थी जो नहीं हुई।

**पत्रकार को कार से कुचलने का प्रयास**

ज्ञात हो कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर खेती करने के मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने तथा उक्त मामले की खबर अखबार में प्रकाशित करने से नाराज अतिक्रमणकारी ने पत्रकार पर जानलेवा हमला करते हुए उसे कार से कुचलने का प्रयास किया जिसकी शिकायत पत्रकार द्वारा बसंतपुर थाने में दी गई है। वाइफनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत बसंतपुर में स्थित शासकीय भूमि पर स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर दिनेश यादव व अन्य के द्वारा कब्जा किया गया था जिसकी शिकायत करने पर तहसीलदार ने भूमि पर निर्माण या खेती करने पर रोक लगा दी थी इसके बाद भी भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने खेती कर दी इस संबंध में रिहन्द टाइम्स द्वारा खबर का प्रकाशन किया गया था वहीं प्रशासन द्वारा खबर को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करते हुए खेती को जप्त कर पंचायत के सुपुर्द कर दिया गया। इससे अतिक्रमणकारी दिनेश यादव द्वारा बसंतपुर में अखबार के प्रतिनिधि पत्रकार रामहरि गुप्ता से द्वेष रखते हुए उसे धमकी दी जा रही थी आज सुबह जब पत्रकार रामहरि गुप्ता गांव के सोसयटी दुकान से पैदल अपने घर की ओर जा रहा था उसी समय हाईस्कूल की ओर से दिनेश यादव अपनी कार से आ रहा था रामहरि गुप्ता को देखकर उसने अचानक कार की रफतार बढ़ा दी तथा उसपर कार चलाये का प्रयास किया। तेज रफतार में अपनी ओर कार को आता देखकर सतर्क हो चुके रामहरि गुप्ता ने एक और छलांग लगाकर स्वयं को बचाया।

**पत्रकार पर जानलेवा हमला का आरोप**

बता दें कि बालोद जिले के गुरुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक पत्रकार पर कालिलाना हमला हुआ जिसके बाद पत्रकार अधमरे हालत में कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती भी रहा, लेकिन गुरुर पुलिस थाना प्रभारी तूल सिंह पट्टवी के द्वारा कई दिन बीत जाने के बाद भी हमलावर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जाह्नपुरी के मुताबिक गुरुर पुलिस थाना प्रभारी तूल सिंह पट्टवी द्वारा आरोपियों को जान बूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था जिससे कि पत्रकार पर जानलेवा हमले के आरोपी कोर्ट से अग्रिम जमानत ले सके। थाना प्रभारी अपने मंसूबे में सफल भी रहे जिसके बाद पत्रकार पर हुए कालिलाना हमले के मुख्य आरोपी पूर्व विधायक धैष्या राम सिन्हा ने कोर्ट से अग्रिम जमानत भी ले ली।

**राजधानी रायपुर में वरिष्ठ पत्रकार के अपहरण का प्रयास**

राजधानी रायपुर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला वरिष्ठ पत्रकार मनोज शुक्ला के अपहरण और महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार का है। इस गंभीर मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों पर मात्र मामूली धाराएं लगाकर पछा झाड़ने की घटना ने पत्रकारों में आक्रोश पैदा कर दिया है।



# क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?

**कलम बंद...का 55 वां दिन**

?

**कलम बंद...का 55 वां दिन**



घटती-घटना के सैही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

## खुला पत्र

देश के माननीय प्रधानमंत्री से भी सवाल...क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार के खिलाफ समाचार लिखना है अपराध ?

अम्बिकापुर, 25 अगस्त 2024 (घटती-घटना)। माननीय मुख्यमंत्री से भी सवाल है...छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है...केन्द्र में भी आपकी पार्टी की सरकार है...पर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमियां दिखाने से रोकने का भी प्रयास हो रहा है...यह प्रयास कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है...जहां पर भाजपा सरकार से लोगों को बेहतर करने की उम्मीद होती है तो वहीं पर छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित मंत्री, विधायक बे-लगाम हो चुके हैं...उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ दिख रहे हैं...उनकी कमियों को बताना उन्हें रास नहीं आ रहा इसलिए वह पत्रकार, संपादक का कलम बंद करने का प्रयास कर रहे हैं अब इस पर आप ही संज्ञान ले...और बताएं की संपादक व पत्रकार कौन सी खबर प्रकाशित करें ?

## क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?



कलम  
बंद...

कलम  
बंद...का  
55 वां  
दिन

कलम  
बंद...का  
55 वां  
दिन

कलम  
बंद...

घटती-घटना के सही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह

खुला पत्र

# भारत में सच्चे पत्रकार को राजनीतिक पार्टियों से खतरा क्यों रहता है ?

अम्बिकापुर, 25 अगस्त 2024 (घटती-घटना)। भारत अपने पत्रकारों को निडर होकर काम करने का स्वतंत्र तरीका प्रदान करने में बहुत पीछे है... इन दिनों... कुछ को छोड़कर... हर दूसरा पत्रकार वही खबर दे रहा है जो सरकार की प्रशंसा करती है... नए चैनल लोगों को सरकार द्वारा की गई गलती से विचलित करने के लिए विभिन्न विषयों पर अनावश्यक बहस दिखाएंगे... इसके कारण, अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो किसी का ध्यान नहीं जाता हैं... दूसरा कारण यह है कि पत्रकार अपने सिद्धांतों और मूल्यों को खो रहे हैं क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि स्थापना के खिलाफ विषयों पर बोलने या लिखने वाले पत्रकारों को धमकी देना, गाली देना और मारना कई अन्य देशों की तरह भारत में भी एक वास्तविकता बन गई है... देश और दुनिया को डरा दिया है... वहीं, पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है... जो पत्रकार देश और उसके आम नागरिकों के लिए लिखे वे मरे या प्रताड़ित हुए सरकारी तंत्रों के द्वारा...!

## क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?



कलम  
बंद...का  
55 वां  
दिन

कलम  
बंद...



कलम  
बंद...का  
55 वां  
दिन

कलम  
बंद...



घटती-घटना के सही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

खुला पत्र

# क्या भ्रष्टाचार का मामला वहीं होगा दर्ज जहां होगी भाजपा से इतर दल की सरकार ?

» भ्रष्टाचार की खबरों से दिक्कत...  
» कमी दिखाओ तो दिक्कत...  
» जनता की परेशानियों को दिखाओ तो दिक्कत...

अम्बिकापुर ,25 अगस्त 2024(घटती-घटना)।  
आखिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करें तो क्या

करें ? सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने पत्रकार दौड़ रहा पर पत्रकार की दौड़ के पीछे निर्वाचित जनप्रतिनिधि उसकी दौड़ की गति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं,भ्रष्टाचार बढ़ता रहे पर पत्रकार ना दिखाएं क्या यही चाहता है जनप्रतिनिधि या फिर सरकारी तंत्र।

# क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?



कलम बंद...का 55 वां दिन

कलम बंद...का 55 वां दिन



घटती-घटना के सही पाठकों,विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...





# तुगलकी फरमान के विरुद्ध कलम बंद अभियान का 55 वां दिन

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विभाग जनसंपर्क के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल के विभाग के संबंधित समाचारों के प्रकाशन पर जनसंपर्क संचालक आर्इपीएस श्री मयंक श्रीवास्तव के मौखिक आदेश पर घटती-घटना के शासकीय विज्ञापन पर रोक लगाकर दबाव बनाने से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मूलभूत हक पर कुठाराघात के विरुद्ध कलमबंद अभियान...के पन्द्रहवें दिन भी केंद्र सरकार से अनुमोदित विज्ञापन नियमावली के आदेश को ठेंगा दिखाने वाले जनसंपर्क विभाग के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के पीछे किसका हाथ...

## क्या छापें स्वास्थ्य मंत्री जी ?

क्या छापें आयुक्त सहसंचालक आर्इपीएस मयंक श्रीवास्तव जी ?



संविधान हत्या दिवस 25 जून  
क्या छत्तीसगढ़ में भी मनेगा ?

छत्तीसगढ़ सरकार घर तोड़िए या  
कार्यालय तोड़िए...इंकलाब होता

रहेगा इंसाफ तक...

अब तो बताईए मुख्यमंत्री जी...क्या छापें ?

## क्यूं न लिखें सच ?

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी  
25 जून को संविधान हत्या दिवस  
छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जायेगा क्या ?

इमरजेंसी पर बात...हर बात पर  
आरोप...तो छत्तीसगढ़ में एक आर्इपीएस  
के तुगलकी फरमान पर आदिवासी  
अंचल से विगत 20 वर्षों से प्रकाशित

अखबार पर क्यों किया जा  
रहा है जुर्म... ?

क्यों कलमबंद आंदोलन के लिए विवश  
होना पड़ा एक दैनिक अखबार को... ?

घटती-घटना के सही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह